

सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम

बनाम

मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

17 अक्टूबर, 2011

[डी.के. जैन और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्या.]

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम,
1988

नियम 2(1)(एफ), 4(1)(2) और 10- लेनदेन मूल्य- आयात कच्चे
सूरजमुखी के बीज के तेल का- अनुबंध 26.6.2001 को संपन्न हुआ-
वास्तविक शिपमेंट 5.8.2001 को हो रहा है- इस बीच आयातित वस्तुओं
की कीमत में वृद्धि- निर्धारित दाखिल अनुबंध मूल्य के अनुसार दस्तावेज़-
राजस्व को अस्वीकार करना अनुबंध मूल्य और सीमा शुल्क की मांग के
अनुसार समसामयिक चालान मूल्य जिस पर अन्य आयातकों ने प्रवेश
किया एक ही वस्तु या एक ही वस्तु की आपूर्ति के लिए अनुबंध में
आपूर्तिकर्ताओं या उसी देश में अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ- आयोजित:
धारा 14(1) नियम 4 के साथ प्रदान करता है कि भुगतान की गई कीमत
आयातक को वाणिज्य के सामान्य पाठ्यक्रम में लिया जाएगा किसी विशेष

परिस्थिति के अभाव में मूल्य होना धारा 14(1) में दर्शाया गया है- इसलिए, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए मूल्य वास्तव में कीमत है व विशेष लेनदेन के लिए भुगतान किया, जब तक कि कीमत न हो नियम 4(2) में निर्धारित कारणों से अस्वीकार्य- तत्काल में मामला, हालांकि इसमें शामिल वस्तु में अस्थिर उतार-चढ़ाव था अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में देरी हो रही है शिपमेंट, आपूर्तिकर्ताओं ने कीमत में वृद्धि नहीं की जी क्मोडिटी की कीमत में बढ़ोतरी के बाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार- इसलिए, राजस्व उचित नहीं था। उत्तरदाताओं द्वारा घोषित लेनदेन मूल्य को अस्वीकार करने में उनके द्वारा प्रस्तुत चालान में- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962- धारा 14

शब्दों और वाक्यांशों:

अभिव्यक्तियाँ 'सामान्यतः' तथा 'संशय का कारण'- का अर्थ

26.6.2001 को, प्रतिवादी ने सी ए सं. 2521/2006 में आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक अनुबंध किया दर पर 500 मीट्रिक टन कच्चे सूरजमुखी के बीज का तेल यूएस \$ 435 सीआईएफ/मीट्रिक टन। माल वास्तव में थे 5.8.2001 को भेजा गया। की धारा 10ए के तहत एक मांग पत्र सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित की कीमत का निर्धारण माल) नियम, 1988 (सीवीआर, 1988) सी को जारी किया गया था प्रतिवादी ने कहा कि जब वास्तविक शिपमेंट हुआ, मूल शिपमेंट अवधि की समाप्ति के

बाद, कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य था और इसलिए, अनुबंध मूल्य सी.वी.आर. 1988 के नियम 4 के संदर्भ में 'लेन-देन मूल्य' के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निर्णायक प्राधिकारी ने पुष्टि की मांग की और प्रतिवादी को शुल्क की विभेदक राशि भुगतान करने का आदेश दिया। प्रतिवादी की अपील आयुक्त (अपील) द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि ट्रिब्यूनल ने माना है कि चालान कीमत को नजरअंदाज करते हुये विभेदक राशि भुगतान करने की मांग का कोई आधार नहीं है। व्यथित होकर राजस्व ने अपील दायर की। अन्य अपीलें भी थीं समान तथ्यों और परिस्थितियों में दायर किया गया।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारितन किया:

1.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(1) के अनुसार, की शुल्क का निर्धारण माल के मूल्य पर किया जाना है। धारा 14(2) के तहत मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा कता है। जहां मूल्य निश्चित नहीं है वहां धारा 14(1) के तहत निर्णय लिया जाना है। धारा 14(1) के अनुसार मूल्य, वह कीमत मानी जाएगी जिस पर ऐसा या जैसे सामान आम तौर पर बेचा जाता है या बिक्री के लिए पेश किया जाता है समय और स्थान पर डिलीवरी और आयात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्रम शब्द "सामान्यतः" तात्पर्य विशेष परिस्थितियों के बहिष्कार से है। यह एस में अंतिम वाक्य द्वारा एक स्थिति स्पष्ट की जाती है। 14(1) जो एक

"साधारण" बिक्री का वर्णन करता है जहां विक्रेता या खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री या बिक्री की पेशकश के लिए कीमत ही एकमात्र विचार है। इसलिए, जब समय के संबंध में स्थितियाँ, स्थान और विशेष परिस्थितियों की अनुपस्थिति पूरी होने पर, आयातित वस्तुओं की कीमत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित धारा 14(1 ए) के तहत तय की जाएगी। उक्त नियम सीवीआर 1988 हैं। [पैरा 12] [1141-ई-एच; 1142-ए-बी]

आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड, हरियाणा बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई 2000 (4) आपूर्ति। एससीआर 597 2000 (122) ई.एल.टी. 321 (एससी): 2001 (1) एससीसी 315; सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), मुंबई बनाम। अब्दुल्ला कोयलोथ 2010 (13) एससीआर 280 (2010) 13 एससीसी 473- पर निर्भर।

1.2 आर के अनुसार। सीवीआर 1988 के 2(1)(एफ), "लेन-देन मूल्य" का अर्थ उसके आर.4 के अनुसार निर्धारित मूल्य है। [पैरा 10] [1138-एफ]

1.3 आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड में, यह माना गया है कि ऐसे मामलों में जहां आरआर.4(2)(सी) से (एच) में उल्लिखित परिस्थितियां लागू नहीं हैं, विभाग लेनदेन मूल्य के तहत शुल्क का आकलन करने के लिए बाध्य है। इसलिए, जब तक कि किसी विशेष लेनदेन के लिए वास्तव में भुगतान

की गई कीमत आरआर.4(2)(सी) से (एच) में उल्लिखित अपवादों के अंतर्गत नहीं आती है, विभाग लेनदेन मूल्य पर शुल्क का आकलन करने के लिए बाध्य है। आगे यह माना गया कि आर.4 सीधे अधिनियम की धारा 14(1) से संबंधित है। [पैरा 12] [1142-बी-सी] ई एफ

1.4 आर.4 के साथ पठित धारा 14(1) में प्रावधान है कि वाणिज्य के सामान्य पाठ्यक्रम में आयातक द्वारा भुगतान की गई कीमत धारा 14(1) में निर्दिष्ट किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में जी को मूल्य माना जाएगा। इसलिए, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए मूल्य के रूप में जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह वास्तव में विशेष लेनदेन के लिए भुगतान की गई कीमत है, जब तक कि कीमत आर.4(2) में निर्धारित एच कारणों के लिए अस्वीकार्य न हो। [पैरा 12] [1142-सी-ई]

सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम 1131 बनाम अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

रवीन्द्र चंद्र पॉल बनाम. सीमा शुल्क आयुक्त ए (निवारक), शिलांग 2007 (3) एससीआर 319 = (2007) 3 एससीसी 93- पर भरोसा किया गया।

1.5 फिर भी, यदि कुछ के आधार पर समसामयिक साक्ष्य, राजस्व करने में सक्षम है प्रदर्शित करें कि चालान सही को प्रतिबिंबित नहीं करता है मूल्य, चालान मूल्य को अस्वीकार करना उचित होगा और उसके

अनुसार लेनदेन मूल्य निर्धारित करें सीवीआर 1988 में निर्धारित प्रक्रिया। अस्वीकार करने से पहले आयातक द्वारा घोषित लेनदेन मूल्य गलत या अस्वीकार्य, राजस्व को सी पर लाना होगा उसे समसामयिक दिखाने के लिए ठोस सामग्री रिकॉर्ड करें आयात, जिसमें स्पष्ट रूप से की तारीख शामिल होगी अनुबंध, आयात का समय और स्थान आदि, एक पर थे उच्चतम मूल्य। ऐसी स्थिति में सीवीआर 1988 का आर.10ए विचार करता है कि विभाग के पास 'डी' का कारण कहां है घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता पर संदेह हो सकता है आयातक से और अधिक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहे प्रभाव यह है कि घोषित मूल्य कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान किया गया या देय। [पैरा 11] [1140-ए-एच; 1141-ए]

1.6 हालाँकि, 'संदेह करने का कारण' का अर्थ 'संदेह करने का कारण' नहीं है। किसी आयातक द्वारा उत्पादित चालान की शुद्धता पर मात्र संदेह इसे आयातित माल के मूल्य के प्रमाण के रूप में अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया संदेह कुछ भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए और केवल संदेह या अटकल पर आधारित नहीं होना चाहिए। यद्यपि साक्ष्य के सख्त नियम अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को जी पर दस्तावेजों के संभावित मूल्य की जांच करनी होती है जिस पर राजस्व द्वारा निर्भरता की मांग की जाती है। यह अच्छी तरह से

स्थापित है कि कम मूल्यांकन को साबित करने की जिम्मेदारी राजस्व पर है, लेकिन एक बार जब राजस्व उच्च कीमत पर समसामयिक आयात के साक्ष्य पेश करके सबूत के बोझ से मुक्त हो जाता है, तो जिम्मेदारी यह आयातक को यह स्थापित करने के लिए स्थानांतरित करता है कि उसके द्वारा भरोसा किए गए चालान में दर्शाई गई कीमत सही है। [पैरा 11]

[1141-ए-डी]

1.7 मौजूदा मामले में, पूरा विवाद एक ही वस्तु की कीमत में अंतर के कारण उत्पन्न हुआ, बी ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग अनुबंधों के तहत आपूर्ति करने का अनुबंध किया था। माना जाता है कि कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल की आपूर्ति का अनुबंध @ यूएस \$ 435 सीआईएफ/पीएमटी पर 26.6.2001 को किया गया था। इसे समय पर निष्पादित नहीं किया जा सका जिसके कारण अनुबंधित पक्षों के बीच शिपमेंट के लिए समय सी के विस्तार पर सहमति बनी। यह सच है कि इसमें शामिल वस्तु की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत में अस्थिर उतार-चढ़ाव था, लेकिन शिपमेंट में देरी होने के कारण, आपूर्तिकर्ता ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में डी वृद्धि के बाद भी वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं की। यह तथ्य आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई वास्तविक राशि से भी साबित होता है। आपूर्तिकर्ता और आयातक होने का कोई आरोप नहीं है। मिलीभगत से. यह राजस्व का मामला भी नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए लेन-देन का मूल्य कम था या वह वास्तविक नहीं

था। न ही आयातित माल का गलत विवरण था। यह भी राजस्व का मामला नहीं है कि विषयगत आयात सीवीआर 1988 के आर.4(2) में उल्लिखित किसी भी स्थिति में आता है। राजस्व द्वारा भरोसा किए गए आयात उदाहरणों को समसामयिक मूल्य का संकेत देने वाले उदाहरणों के रूप में नहीं माना जा सकता है। माल क्योंकि उन मामलों में माल की आपूर्ति के लिए अनुबंध तत्काल मामलों में अनुबंध की तारीख से लगभग एक महीने के बाद दर्ज किए गए थे, और भी अधिक, जब स्वीकार्य रूप से शामिल वस्तु की अंतरराष्ट्रीय कीमत में भारी उतार-चढ़ाव थे। [पैरा 13] [1142-एफ-एच; 1143-ए-सी-डी-एफ]

1.8 इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि लेनदेन को अस्वीकार करना राजस्व उचित नहीं था। उत्तरदाताओं द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत चालान एच में घोषित मूल्य। [पैरा 13] [1143-एफ]

केस कानून संदर्भ:

2000 (4) सप्ल. एससीआर 597	पर भरोसा 6 के लिए
2010 (13) एससीआर 280	पर भरोसा 8 के लिए
2007 (3) एससीआर 319	पर भरोसा 12 के लिए

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2521/2006।

उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय

पीठ के अपील संख्या सी/139/02 में सीमा शुल्क, के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 04.08.2005 से उत्पन्न।

साथ

सिविल अपील संख्या 1699, 2129, 2114, 2518, 2519, 2520, 2522, 2523, 2853, 3197, 3487, 2006 की 3564 और 2007 की 5006

आर.पी. भट्ट, श्याम दीवान, शिप्रा घोष, बीनू टम्टा, बी. कृष्णा प्रसाद, पी. परमेश्वरन, वी.के. वर्मा. प्रमोद बी.. अग्रवाला, प्रवीणा गौतम, अनुज पी. अग्रवाला, कैलाश पांडे, रणजीत सिंह, के.वी. श्रीकुमार, एम. गिरीश कुमार, के. परमेश्वर, ख्वायरकपम नोबिन सिंह, एस. नंदा कुमार, अंजलि चौहान, सतीश कुमार, परिवेश सिंह और वी.एन. रघुपति उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डी. के. जैन, जे.:

1. अपीलों का यह समूह अपील संख्या सी/139-140/02: सी/209/02 में दिनांक 4 अगस्त, 2005 के अंतिम आदेशों से उत्पन्न हुआ है; सी/288/03; सी/291-93/03; सी/299/03; सी/243/02; सी/264/02 एवं सी/313/03; 5 अगस्त, 2005 को अपील संख्या सी/265/03 में, 22 जून 2005 को अपील संख्या सी/213/02 में और 29 दिसंबर, 2006 को अपील संख्या सी/300/03 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलकर्ता

द्वारा पारित किया गया। ट्रिब्यूनल साउथ जोनल बेंच, बेंगलोर (संक्षेप में "ट्रिब्यूनल")। आक्षेपित आदेशों के द्वारा, ट्रिब्यूनल ने उत्तरदाताओं-आयातकों द्वारा की गई अपीलों को अनुमति दे दी है।

2. चूंकि सभी अपीलों में कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए इनका निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि, विवाद की सराहना करने के लिए, सी.ए. से सामने आए तथ्य। 2006 की संख्या 2521, जिसे मुख्य मामला माना गया था, को विज्ञापित किया जा रहा है। ये इस प्रकार हैं:

“26 जून 2001 को, प्रतिवादी ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं जैसे मैसर्स विल्मर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया। लिमिटेड, सिंगापुर, यूएस \$ 435 सीआईएफ/मीट्रिक टन की दर पर 500 मीट्रिक टन कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात के लिए। अनुबंध के तहत, खेप को जुलाई 2001 के महीने में भेजा जाना था, लेकिन चूंकि शिपमेंट के लिए पारस्परिक रूप से सहमत समय को 31 जुलाई 2001 के परिशिष्ट के माध्यम से 'मध्य अगस्त 2001' तक बढ़ा दिया गया था, माल वास्तव में 5 अगस्त 2001 को भेजा गया था। प्रवेश के बिल को दाखिल करने के बाद, सामान का अनंतिम मूल्यांकन किया गया,

समकालीन मूल्य, मूल दस्तावेजों और सरकारी रासायनिक परीक्षक से परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन लंबित था।"

3. दायर किए गए दस्तावेजों के सत्यापन पर, निर्णायक प्राधिकारी ने शिपमेंट अवधि में कुछ विसंगतियां देखीं। ई तदनुसार, 5 अक्टूबर 2001 को, उन्होंने सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988 (संक्षेप में "सीवीआर 1988") के नियम 10 ए के तहत प्रतिवादी को एक मांग पत्र जारी किया ताकि यह बताया जा सके कि अनुबंध क्यों किया गया कीमत अस्वीकार नहीं की जाएगी और सीमा शुल्क का निर्धारण समसामयिक चालान कीमत को अपनाकर नहीं किया जाएगा जिस पर अन्य आयातकों ने उसी वस्तु की आपूर्ति के लिए उसी आपूर्तिकर्ता या उसी देश में अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध किया था। चूंकि कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोप का महत्वपूर्ण असर है शामिल मुद्दे के निर्धारण पर, नोटिस का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"दिनांक 26.6.2001 के अनुबंध में शामिल शर्त के अनुसार, माल जुलाई 2001 के महीने के दौरान भेजा जाना है। जबकि माल शिपमेंट अवधि की समाप्ति के बाद यानि 5.8.01 को भेजा गया था। वास्तविक शिपमेंट के समय तक अगस्त 2001 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एल.ई

सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम 1135 वी. अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (डी.के. जैन, जे.) कच्चे सूरजमुखी बीज तेल (खाद्य ए ग्रेड) की बाजार कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988 के नियम 4 के साथ पढ़ी गई धारा 14(1) के अनुसार अनुबंध मूल्य स्वीकार्य नहीं है।"

4. संक्षेप में, राजस्व का मामला यह था कि जब वास्तविक शिपमेंट हुआ, तो मूल शिपमेंट अवधि की समाप्ति के बाद, कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत में भारी वृद्धि हुई थी, और इसलिए, अनुबंध मूल्य नहीं हो सका सीवीआर 1988 के नियम 4 के संदर्भ में 'लेन-देन मूल्य' के रूप में स्वीकार किया गया।

5. जवाब में, प्रतिवादी की दलील थी कि अनुबंध में शिपमेंट के लिए समय के विस्तार की परिकल्पना की गई थी, लेकिन निर्यातक शिपमेंट में एक महीने की देरी के बावजूद सहमत मूल्य पर तेल की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था और इसके अलावा किसी सबूत के अभाव में डी यह दिखाने के लिए कि उन्होंने खेप के लिए निर्यातक को अतिरिक्त कीमत का भुगतान किया है या भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, लेनदेन मूल्य को चालान मूल्य होना चाहिए। हालाँकि, उक्त याचिका को निर्णय

प्राधिकारी का समर्थन नहीं मिला। तदनुसार, उन्होंने मांग ई पत्र में दर्शाई गई मांग की पुष्टि की और प्रतिवादी को शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। प्रतिवादी की आयुक्त (अपील) के समक्ष पहली अपील असफल रही।

6. आयुक्त (अपील) के आदेश से असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी मामले को ट्रिब्यूनल में आगे की अपील में ले गया। जैसा कि पूर्वोक्त है, हमारे समक्ष मामलों में लागू सामान्य आदेश द्वारा, ट्रिब्यूनल ने आयुक्त (अपील) के आदेश को रद्द कर दिया है और माना है कि चालान मूल्य की अनदेखी करके अंतर शुल्क की मांग का कोई आधार नहीं था। आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड, हरियाणा बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई, ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार कहा:

"उपर्युक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है

1. 2000 (122) ई.एल.टी. 321 (एससी): (2001) 1 एससीसी 315 कि 'विशेष परिस्थितियों' के अभाव में, आयातित माल की कीमत सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के अनुसार धारा 14(1)(ए) के तहत निर्धारित की जानी है। 'विशेष परिस्थितियों' को नियम 4(2) में वैधानिक रूप से विशिष्ट किया गया है) और इन अपवादों के अभाव में, सीमा शुल्क विभाग के लिए विशेष लेनदेन में माल के

लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत को स्वीकार करना अनिवार्य है। सभी मामलों में, हम पाते हैं कि लेन-देन का मूल्य पूरी तरह से अनुबंधों के आधार पर वाणिज्यिक विचारों पर निकाला गया है। आपूर्तिकर्ता ने, अनुबंधों का सम्मान करने के लिए, अनुबंधित मूल्य पर माल की आपूर्ति की। ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने आपूर्तिकर्ता को अनुबंधित मूल्य से अधिक का भुगतान किया। इन परिस्थितियों में, लेनदेन मूल्य को अस्वीकार करने का वास्तव में कोई आधार नहीं है।"

7. इसलिए ये अपीलें राजस्व द्वारा हैं।

8. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.पी. भट्ट ने कहा कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के कब्जे में मौजूद चालानों के आलोक में, बहुत अधिक कीमत पर कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के समसामयिक आयात को दर्शाते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को न्यायोचित ठहराया गया था। सीवीआर 1988 के नियम 10ए को लागू करने में और प्रतिवादी-आयातक द्वारा घोषित चालान मूल्य को अस्वीकार करने में। यह तर्क दिया गया कि समकालीन चालानों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि माल की वास्तविक शिपमेंट के समय, अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य बहुत अधिक था और इसलिए, प्रतिवादी द्वारा घोषित लेनदेन मूल्य

सीवीआर 1988 के नियम 4 के संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा शुल्क आयुक्त (जनरल), मुंबई बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। विद्वान वरिष्ठ वकील अब्दुल्ला कोयलोथ ने तर्क दिया कि ठोस समसामयिक आयातों के आलोक में, माल की शिपमेंट की तारीख के अनुसार समान वस्तुओं की बहुत अधिक बाजार कीमत दिखाते हुए, लेनदेन मूल्य को धारा 14(1) के संदर्भ में सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। सीवीआर 1988 का नियम 4(2) ई।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के निष्पादन के समय कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल का बाजार मूल्य दिखाने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में चालान में दर्ज की गई राशि से अधिक था, निर्णायक प्राधिकारी के पास बी की वास्तविकता या घोषित मूल्य की सटीकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, ताकि सीवीआर 1988 के नियम 10 ए को आकर्षित किया जा सके। यह बताया गया था कि विशेष के खंड 7 के तहत अनुबंध के तहत शर्तें, प्रतिवादी और विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच दर्ज की गईं, प्रतिवादी शिपमेंट की अवधि बढ़ाने के लिए बाध्य था और इसलिए, 31 जुलाई, 2001 के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत, शिपमेंट की अवधि में बदलाव को छोड़कर सभी कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल की कीमत सहित अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहीं। यह तर्क दिया गया कि राजस्व द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई

किसी भी सामग्री के अभाव में यह संकेत मिलता है कि अनुबंध की तारीख, यानी 26 जून 2001 को, कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल का बाजार मूल्य अनुबंधित मूल्य से अधिक था, कोई विशेष नहीं सीवीआर 1988 के नियम 4 के उप-नियम 2 में उल्लिखित परिस्थितियों को आकर्षित किया गया था और इस प्रकार, राजस्व लेनदेन मूल्य के रूप में चालान मूल्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य था।

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने से पहले, प्रासंगिक प्रावधानों पर एक विहंगम दृष्टि डालना उपयोगी होगा। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 (संक्षेप में "अधिनियम"), जहां तक यह वर्तमान अपीलों के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है: एफ

“14. मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन।-

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए जिसके तहत किसी भी सामान पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। उनके मूल्य के संदर्भ में, ऐसे माल का मूल्य माना जाएगा- वह कीमत जिस पर आम तौर पर ऐसा या उसके जैसा सामान बेचा जाता है, या बिक्री के लिए पेश किया जाता है, जैसा भी मामला हो, आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के

दौरान, जहां विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री या बिक्री की पेशकश के लिए कीमत ही एकमात्र विचार है:

बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी, जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल प्रस्तुत किया जाता है, या शिपिंग बिल या निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाता है। धारा 50;

(1 ए) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं के संबंध में उस उपधारा में निर्दिष्ट कीमत इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ए) में किसी भी बात के बावजूद, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, टैरिफ मान तय कर सकती है। आयातित माल या निर्यात माल के किसी भी वर्ग, ऐसे या समान माल के मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, और जहां

ऐसे कोई टैरिफ मूल्य तय किए गए हैं, शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में लगाया जाएगा।"

सीवीआर 1988 के नियम 2(1)(1) के अनुसार "लेनदेन मूल्य" का अर्थ सीवीआर 1988 के नियम 4 के अनुसार निर्धारित मूल्य है। नियम 4 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"4. लेन-देन मूल्य। (1) आयातित माल का लेन-देन मूल्य भारत में निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत होगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त उप-नियम एच (1) के तहत आयातित वस्तुओं का लेनदेन मूल्य स्वीकार किया जाएगा:

उसे उपलब्ध कराया-

ए- बिक्री पूर्णतः प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में व्यापार के सामान्य क्रम में होती है;

बी- बिक्री में सामान्य प्रतिस्पर्धी मूल्य से कोई असामान्य छूट या कमी शामिल नहीं है;

सी- बिक्री में विशिष्ट एजेंटों तक सीमित विशेष छूट शामिल नहीं है;

डी- नियम 9 के प्रावधानों के तहत लेनदेन मूल्य में किए जाने वाले आवश्यक समायोजन के संबंध में उद्देश्यपूर्ण और मात्रात्मक डेटा मौजूद है;

इ- क्रेता द्वारा माल के निपटान या उपयोग पर प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है-

i. भारत में कानून या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए या आवश्यक हैं;

या

ii. उस भौगोलिक क्षेत्र को सीमित करें जिसमें सामान दोबारा बेचा जा सके; या

iii. माल के मूल्य पर पर्याप्त प्रभाव न डालें;

एफ- बिक्री या कीमत उसी शर्त या विचार के अधीन नहीं है जिसके लिए मूल्यांकित वस्तुओं के संबंध में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है;

जी- खरीदार द्वारा माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेता को जमा नहीं होगा, जब तक कि इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन नहीं किया जा सकता है; और

एच- खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं, या जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, वह लेनदेन मूल्य उप-नियम (3) के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है।"

11. धारा 14(1) और 14(1ए) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यथामूल्य शुल्क सी के लिए प्रभार्य किसी भी सामान का मूल्य धारा 14(1) में निर्दिष्ट मूल्य माना जाता है। कार्यवाही करना। धारा 14(1) एक मानद प्रावधान है क्योंकि यह ऐसे सामानों के मानित मूल्य की बात करता है। ऐसी कीमत का निर्धारण प्रासंगिक नियमों के अनुसार और अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। संयुक्त रूप से पढ़ें, अधिनियम की धारा 14(1) और सीवीआर 1988 के नियम 4 दोनों में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 14 (1) में इंगित और सीवीआर 1988 के नियम 4(2) में विशिष्ट किसी भी विशेष परिस्थिति के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के सामान्य पाठ्यक्रम में आयातक द्वारा विक्रेता को भुगतान की गई या देय कीमत को लेनदेन मूल्य माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, नियम 4 के उप-नियम (2) के परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, चालान मूल्य लेनदेन मूल्य के निर्धारण का आधार बनेगा। फिर भी, यदि कुछ समसामयिक साक्ष्यों के आधार पर, राजस्व यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि चालान एफ सही कीमत को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो चालान मूल्य को अस्वीकार करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेनदेन मूल्य निर्धारित करना उचित

होगा। सीवीआर 1988। इस बात पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है कि आयातक द्वारा गलत या अस्वीकार्य घोषित लेनदेन मूल्य को खारिज करने से पहले, जी राजस्व को समकालीन आयात दिखाने के लिए रिकॉर्ड ठोस सामग्री लानी होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुबंध की तारीख, समय और शामिल होगा। आयात का स्थान इत्यादि अधिक कीमत पर थे। ऐसी स्थिति में, सीवीआर 1988 का नियम 10 ए इस बात पर विचार करता है कि जहां विभाग के पास घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता पर 'संदेह का कारण' है, वह डीई से पूछ सकता है।

आयातक को इस आशय का और स्पष्टीकरण देना होगा कि घोषित मूल्य आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि 'संदेह करने का कारण' का अर्थ 'संदेह करने का कारण' नहीं है। किसी आयातक द्वारा उत्पादित चालान की शुद्धता पर मात्र संदेह इसे आयातित बी माल के मूल्य के प्रमाण के रूप में अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारी द्वारा रखा गया संदेह कुछ भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए और केवल संदेह या अटकल पर आधारित नहीं होना चाहिए। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि यद्यपि साक्ष्य के सख्त नियम अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास दस्तावेजों के संभावित मूल्य की जांच करने के लिए सी है, जिस पर राजस्व द्वारा निर्भरता की

मांग की जाती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कम-मूल्यांकन साबित करने की जिम्मेदारी राजस्व पर है, लेकिन एक बार जब राजस्व उच्च कीमत पर समसामयिक आयात के सबूत पेश करके सबूत के बोझ का निर्वहन करता है, तो डीओनस आयातक पर स्थानांतरित हो जाता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि कीमत में संकेत दिया गया है। जिस चालान पर उसने भरोसा किया वह सही है।

12. आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड (सुप्रा) में, ट्रिब्यूनल द्वारा भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने माना था कि आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन का सिद्धांत अधिनियम की धारा 14(1) में पाया जाता है जो ई मूल्यांकन योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय बिक्री मूल्य के आधार पर. उक्त अधिनियम के तहत, वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। धारा 14(1) के अनुसार, शुल्क का निर्धारण माल के मूल्य पर किया जाना है। एफ धारा 14(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा मूल्य तय किया जा सकता है। जहां मूल्य इतना निश्चित नहीं है, उसे धारा 14(1) के तहत तय किया जाना चाहिए। धारा 14(1) के अनुसार, मूल्य को वह कीमत माना जाएगा जिस पर आम तौर पर ऐसे या समान सामान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के लिए। "सामान्यतः" शब्द का तात्पर्य विशेष परिस्थितियों के बहिष्कार से है। इस स्थिति को धारा 14(1) में अंतिम वाक्य द्वारा स्पष्ट किया गया है जो एक

"साधारण" बिक्री का वर्णन करता है जहां विक्रेता या खरीदार को एक दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है या बिक्री के लिए प्रस्ताव. इसलिए, जब समय, स्थान और विशेष परिस्थितियों की अनुपस्थिति से संबंधित उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आयातित वस्तुओं की कीमत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 14(1 ए) के तहत तय की जाएगी। उक्त नियम सीवीआर 1988 हैं। आगे यह भी माना गया कि मामलों में जहां नियम 4(2)(सी) से (एच) में उल्लिखित परिस्थितियां लागू नहीं हैं, विभाग लेनदेन मूल्य के तहत शुल्क का आकलन करने के लिए बाध्य है। इसलिए, जब तक कि किसी विशेष लेनदेन के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत नियम 4(2)(सी) से (एच) में उल्लिखित अपवादों के अंतर्गत नहीं आती है, विभाग बाध्य है।

लेनदेन मूल्य पर शुल्क का आकलन करें। आगे यह माना गया कि नियम 4 सीधे अधिनियम की धारा 14(1) से संबंधित है। नियम 4 के साथ पढ़ी गई धारा 14(1) में प्रावधान है कि वाणिज्य के सामान्य क्रम में आयातक द्वारा भुगतान की गई कीमत को धारा 14(1) में निर्दिष्ट किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में मूल्य माना जाएगा। इसलिए, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए मूल्य के रूप में जो स्वीकार किया जाना चाहिए वह विशेष लेनदेन के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत है, जब तक कि

कीमत नियम 4(2) में निर्धारित कारणों से अस्वीकार्य न हो। (यह भी देखें: रवीन्द्र चंद्र पॉल बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), शिलांग)

13. उपरोक्त सिद्धांतों को मौजूदा तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि राजस्व ने चालान मूल्य को अस्वीकार करने में गलती की है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामले में पूरा विवाद एक ही एफ वस्तु की कीमत में अंतर के कारण उत्पन्न हुआ, जिसकी आपूर्ति अलग-अलग समय पर किए गए विभिन्न अनुबंधों के तहत की गई थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मौजूदा मामले में, माना जाता है कि कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल की आपूर्ति का अनुबंध @ यूएस \$ 435 सीआईएफ / पीएमटी पर 26 जून 2001 को दर्ज किया गया था। जी के कारण इसे समय पर निष्पादित नहीं किया जा सका, जिसके कारण शिपमेंट के लिए समय का विस्तार किया गया था। अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच सहमति हुई। यह सच है कि इसमें शामिल वस्तु की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत में अस्थिर उतार-चढ़ाव था, लेकिन शिपमेंट में देरी होने के कारण, आपूर्तिकर्ता ने एचएस (2007) 3 एससीसी 03 में इसकी कीमत में वृद्धि के बाद भी वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं की।

अंतराष्ट्रीय बाजार. यह तथ्य आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई वास्तविक राशि से भी साबित होता है। आपूर्तिकर्ता और आयातक की मिलीभगत का कोई आरोप नहीं है। यह राजस्व का मामला भी नहीं है कि

प्रतिवादी द्वारा किया गया लेनदेन वास्तविक नहीं था या उसका मूल्य कम था। न ही आयातित माल का गलत विवरण था। यह राजस्व का मामला भी नहीं है कि विषयगत आयात सीवीआर 1988 के नियम 4(2) में बताई गई किसी भी स्थिति के अंतर्गत आता है। पैरा 3 सुप्रा में निकाले गए कारण बताओ नोटिस से यह स्पष्ट है कि अनुबंध मूल्य था सीवीआर सी 1988 के नियम 4 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 14(1) के संदर्भ में निर्णायक प्राधिकारी को केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2001 में जब वास्तविक शिपमेंट हुआ, तब तक तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में भारी वृद्धि हुई थी। नियम 4(1) के तहत लेनदेन मूल्य को अस्वीकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तु की कीमत में भारी वृद्धि और उत्तरदाताओं द्वारा दर्ज किए गए अनुबंधों के तहत आयातित माल के संबंध में चालान में कीमत में अंतर को छोड़कर कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। अगस्त 2001 के महीने में। हमारी राय में, राजस्व पर निर्भर आयात उदाहरणों को माल के समसामयिक मूल्य को दर्शाने वाले उदाहरणों के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन मामलों में माल की आपूर्ति के अनुबंध लगभग एक महीने के बाद दर्ज किए गए थे। वर्तमान मामलों में अनुबंध की तारीख, और भी अधिक, जब माना जाता है कि इसमें शामिल वस्तु की अंतरराष्ट्रीय कीमत में भारी उतार-चढ़ाव थे। इसलिए, हमारी राय है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत चालान में घोषित लेनदेन मूल्य को अस्वीकार करना राजस्व उचित नहीं था।

14. उपरोक्त कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती। सभी अपीलें तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

आर.पी.

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनामिका सारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।